भारतीय जनता पार्टी
दिल्ली प्रदेश
14 पंडित पंत मार्ग

29 नवंबर, 2013

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

भारत ने 21वीं सदी का सबेरा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की एनडीए सरकार में देखा था। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि भारत को 21 वीं सदी में विश्व का नेतृत्व करने योग्य बनाना है। यदि भारत को वैश्विक महाशक्ति बनना है तो भारत का दिल कहे जाने वाली दिल्ली को विकास के पथ पर उसका नेतृत्व करते हुए दिखना चाहिए। परन्तु पिछले 15 वर्षों में एक ही दल और एक ही नेतृत्व की सरकार रहने के बाद भी दिल्ली विकास के उन मानदण्डों पर कहीं पीछे छूट गया जिसकी कल्पना भाजपा ने की थी।

दिल्ली को यदि वास्तविक विकास के मार्ग पर ले जाना है तो हमें अपनी नजर सिर्फ चौड़ी सड़कों, चमचमाती कारों और ऊंचे ऊंचे भवनों से परे ले जाकर उन लोगों पर भी डालनी होगी जो छोटी कॉलोनियों में, सामान्य अवस्था में अथवा उससे भी पीछे जाकर झुग्गी झोपड़ियों में और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही हैं। तभी दिल्ली का सर्वस्पर्शी विकास हो सकता है।

दिल्ली में लाखों असंगठित श्रमिक, घरेलू कामगार, मजदूर, रेहड़ी–फेरी वाले, आवास निर्माण मजदूर, कचरा और कबाड़ी का कार्य करने वाले, ऑटो चालक, रिक्शाचालक, उद्योगों–फैक्ट्रियों और परचून आदि की दुकानों पर 12 घंटे कठोर परिश्रम करके अपनी जीविका कमाते हैं तथा शहर की तरक्की में भरपूर योगदान करते हैं। ये दिल्ली की 1639 अनधिकृत कालोनियों, 860 जेजे क्लस्टर्स, स्लम बस्तियों और खुले आसमान के नीचे सो कर गुजारा करते हैं। दिल्ली में 360 गांव हैं (इस समय गांवों की संख्या बढ़कर लगभग 400 हो गयी है)। राजधानी में 45 पुनर्वास कालोनियां हैं। इन सबमें कुल मिलाकर 49 प्रतिशत दिल्ली की आबादी निवास करती है। भाजपा सत्ता में आने पर इन 49 प्रतिशत लोगों को सम्मानजनक जीवनयापन करने, जीविका कमाने और दिल्ली में आवास बनाने का मौका देगी।

दिल्ली को 21वीं सदी के महान भारत का केन्द्र बनना है तो भारत के हर कोने से आए व्यक्ति की सहभागिता इसमें होगी। भाजपा यह मानती है कि सरकार में वह क्षमता होनी चाहिए कि वह बाहर से आए लोगों को भी एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक उपयोगी मानव संसाधन के रूप में प्रयोग कर सके। मैंने अभी दिल्ली की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले जिन वर्गों का उल्लेख किया है उसमें लगभग सभी प्रवासी हैं।

यदि दिल्ली में हमारी सरकार आई तो हम दिल्ली में निरंतर आने वाले प्रवासियों की समस्या के समाधान और दिल्ली के विकास में उनकी उपयोगी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए एक ''प्रवासी आयोग'' का गठन किया जाएगा। यह आयोग दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों, झुग्गी–झोपड़ीवासियों, जेजे क्लस्टर्स, पुनर्वास कालोनियों, गांवों, खेतिहर मजदूरों, खेतीयोग्य भूमिधारकों और खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोगों के लिए मानवीय व्यवहार करते हुए उनके समुचित आवास, रोजगार, सम्मान आदि की व्यवस्था करने के उपाय सरकार को सुझायेगा। हम यह सिद्ध कर देंगे कि प्रवासी दिल्ली के लिए सपंइपसपजल नहीं बल्कि ेंमजे हैं।

दिल्ली के गरीब और प्रवासी लोगों के कल्याण के लिए डॉ. हर्ष वर्धन ने '**अटल बिहारी वाजपेयी पुनर्वास योजना**' चलाने का निर्णय किया है। अन्य उपाय जो इन लोगों के कल्याण के लिए किये जायेंगे वे इस प्रकार हैं :–

1. नियमों का सरलीकरण और शिथिलीकरण करके भाजपा सभी अनधिकृत (अनियोजित) कालोनियों को सभी बुनियादी, ढांचागत और सम्मानजनक जीवन जीने वाली सुविधायें उपलब्ध करायेगी।
2. सभी झुग्गी–झोपड़ीवासियों, जेजे क्लस्टर्स, स्लमबस्तियों और खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोगों को मानवीय आधार पर पक्के मकान बनाकर पात्र लोगों को पट्टे पर आवंटित किये जायेंगे।
3. सभी 45 पुनर्वास कालोनियों के लाखों निवासियों को उनको दिये गये आवासों का मालिकाना हक तर्कसंगत शर्तों पर सौंपा जायेगा।
4. दिल्ली के सभी गांवों को अत्याधुनिक शहरी गांवों में बदला जाएगा। गांवों में वे सभी सुविधायें दी जाएंगी जो किसी नियोजित शहरी कालोनीवासियों को मिलती हैं।
5. सभी गांववासियों, अनधिकृत कालोनियों के निवासियों, जेजे क्लस्टर्स, स्लमबस्तियों और खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोगों को नये '***कौशल विकास केन्द्र***' खोलकर कौशलयुक्त बनाया जाएगा ताकि वे अपनी पात्रता और योग्यता के अनुसार रोजगार, स्वरोजगार का सम्मानजनक अवसर प्राप्त कर सकें।
6. दिल्ली में हजारों एकड़ कृषि भूमि और यमुना के दोनों तटों पर खादर भूमि है। इस भूमि को दिल्ली के विकास में अतिरिक्त संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। इस भूमि पर हरियाली और नकदी खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस भूमि का संरक्षण हर हाल में किया जाएगा ताकि दिल्ली का भू माफिया इस पर कब्जा न कर सके।
7. गांवों में रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन लोगों को रोजगार, स्वरोजगार तथा आवास उपलब्ध कराये जायेंगे।
8. दिल्ली के सभी गांवों में आबादी का विस्तार तेजी से हुआ है। आबादी की समस्या को गांवों में समायोजित करने के लिए लाल डोरा क्षेत्र का वास्तविकता की जरूरतों के आधार पर गांववार विस्तार किया जाएगा।

9. गांवों और किसानों के लिए परेशान करने वाली दिल्ली लैण्ड रिफार्म एक्ट की धारा 81 और 33 में मानवीय और वास्तविक जरूरतों के आधार पर सुधार किया जाएगा ताकि किसानों और गांववालों का उत्पीड़न समाप्त हो सके।
10. सभी अनधिकृत कालोनियों के लिए विकास के लिए डीडीए की तर्ज पर '***अनधिड्डत कालोनी विकास प्राधिकरण***' का गठन किया जाएगा।
11. गांवों और कृषि योग्य भूमि के उन्नयन और विकास के लिए '***राजधानी ग्रामीण विकास बोर्ड***' का गठन किया जाएगा।
12. राजधानी में स्लम का चलन कांग्रेस की वोट बैंक नीति के कारण हुआ था। इसको कांग्रेस ने ही फलने–फूलने दिया। लोगों को जानबूझकर गरीब और वंचित रखा ताकि वे कांग्रेस के लिए चुनाव के समय पर वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल हो सकें। कांग्रेस के इस षडयंत्र को भाजपा हमेशा के लिए समाप्त करेगी। ऐसी कानूनी और व्यवहारिक व्यवस्था की जाएगी ताकि दिल्ली में भविष्य में कोई भी अनधिकृत कालोनी, अनियोजित कालोनी, जेजे कालोनी, स्लम बस्ती आदि विकसित न हो सकें। इसके लिए शासन स्तर पर अलग से प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। हर कार्य की जवाबदेही और जिम्मेदारी हर स्तर पर तय की जाएगी।
13. दिल्ली में भूमि की कमी है और लोगों के परिवार बढ़ रहे हैं। इस समस्या के निदान के लिए राजधानी में वर्टिकल ग्रोथ की इजाजत मानवीय और व्यवहारिक कानून बनाकर लोगों को दी जाएगी। निजी निर्माण में मास्टर प्लॉन के तहत इस समय वर्टिकल ऊँचाई की सीमा 15 मीटर निर्धारित है। इसे बढ़ाने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा।
14. 100 मीटर या उससे कम के प्लॉट पर नक्शा पास कराने की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी। भविष्य में जो भी सोसायटी या बहुमंजिले फ्लैट बनेंगे, उनमें भूतल को पार्किंग के लिए अनिवार्य किया जाएगा।

मुझे विश्वास है कि विकास के प्रति भाजपा के संकल्प और इसे प्रमाणित करते हुए भाजपा सरकार के अनुभवों और डॉ. हर्षवर्द्धन के निष्कलंक और प्रभावी नेतृत्व के प्रति दिल्ली की जनता विश्वास व्यक्त करेगी और हमें दिल्ली में शानदार सफलता दिलाएगी।